

Resettlement Plan

August 2022

India: Rajasthan State Highway Investment Program – Tranche 3

Package 1: Dantiwara-Pipar to Merta City
Volume 3 of 3, Appendixes 7-9

Prepared by Public Works Department, Government of Rajasthan for the Asian
Development Bank.

CURRENCY EQUIVALENTS

(As of 1 August 2022)

Currency unit –	Indian rupees (₹)
₹1.00 =	\$ 0.026
\$1.00 =	₹79.18

ABBREVIATIONS

ADB	– Asian Development Bank
DC	– District Collector
GOI	– Government of India
GRC	– Grievance Redressal Committee
IAY	– Indira Awaas Yojana
RFCTLARR	– The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
RLAB	– Draft Rajasthan Land Acquisition Bill
NGO	– Nongovernment organization
PD	– Project Director
PIU	– Project Implementation Unit
PRoW	– Proposed Right-of-Way
SDRS	– Social Development and Resettlement Specialist
RoW	– Right-of-Way
SO	– Safeguards Officer
SH	– State Highway
SPS	– Safeguard Policy Statement
SoR	– PWD Schedule of Rate

NOTES

- (i) The fiscal year (FY) of the Government of India and its agencies ends on 31 March. “FY” before a calendar year denotes the year in which the fiscal year ends, e.g., FY2022 ends on 31 March 2022.
- (ii) In this report, "\$" refers to US dollars

This resettlement plan is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. Your attention is directed to the “terms of use” section of this website.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Appendix 7: Public Hearing and Consultation Details

राजस्थान सरकार

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.पी.पी.), पी.आई.यू- जोधपुर

जिला-नागौर, तहसील-मेड़ता में राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेड़ता सिटी) के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्ति अन्तर्गत अधिनियम, 2013 की धारा-5 एवं नियम, 2016 के नियम-7 के प्रावधानानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन (एस0आई0ए0) के तहत जनसुनवाई

तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर

स्थान: राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बीटन, दिनांक: 06/07/2022, समय: प्रातः 11 बजे

उपस्थित अधिकारी:-

क्र0सं0	नाम	पद/विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
(1)	भागीरथ चौधरी	S.D.M. / Revenue	9873970369	
(2)	प्रिया कवारिया	सहायक अभियंता, P.P.P.	8386048030	
(3)	मूलचन्द विश्वाडे	J.A.	7316741240	
(4)	आदिल चौहान	S.A.	9460225574	
(5)	गंगासिंह	I.L.R.	9587210239	
(6)	रामनिवास लुहार	V.D.O. बैठक की कार्यवाही	9460285928	

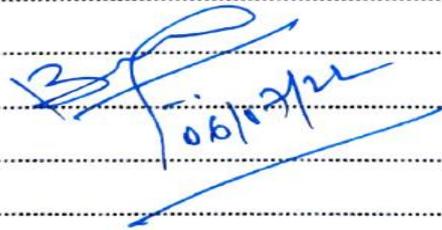
आज दिनांक 06.07.2022 को प्रस्तावित सड़क परियोजना राज्य राजमार्ग संख्या - 21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़ - मेड़ता सिटी) के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन एवं संभावित प्रभाव के परिमाण को निर्धारित करने हेतु उपर्युक्त अधिकारी महोदय मेड़ता की अध्यक्षता में जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम - बीटन, बायड, इंदावड़, मौकलपुर, सातलावास, बासनी रामाचारण एवं मेड़ता के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों ने भाग लिया। जनसुनवाई के दौरान परियोजना अधिकारियों

द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजना, निजी भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव तथा परियोजना कार्यान्वयन हेतु लागू होने वाले नीति-नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पश्चात्, संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों से उक्त परियोजना सड़क हेतु तैयार प्रस्तावित भूमि अवाप्त योजना से उनको होने वाली समस्याओं और सुझाओं को व्यक्त करने का अनुरोध किया गया।

इस क्रम में ग्राम बायड़ के श्री शिवनारायण पुत्र मंगलाराम एवं गोरधनराम पुत्र जैठाराम ने भूमि अवाप्त योजना अनुसार प्रस्तावित खसरा संख्या 581/904, 581, 536/880 में बन्दोबस्त विभाग के स्तर पर सुधार करने की मांग की। ग्राम बीटन के श्री जसाराम पुत्र निम्बाराम, रामनिवास पुत्र दयाराम, सोहनलाल पुत्र शिवलाल, शवणराम पुत्र दयाराम एवं रुपली पत्नी बगदाराम ने सड़क सीमा में स्थित निर्माण / संरचनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की तथा ग्राम बीटन के श्री बाबूलाल पुत्र शंकरराम ने आबादी क्षेत्र में प्रस्तावित 4 लेन सड़क के स्थान पर 2 लेन सड़क निर्माण की मांग रखी। उक्त सभी समस्याओं और सुझाओं पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि बन्दोबस्त विभाग के स्तर पर संबंधित मामलों को प्राथमिकता पर जल्द से जल्द

निस्तारित किया जायेगा, सड़क के प्रभावित भाग का राज्य सरकार की नीति के तहत अनुलोष दिया जायेगा। उपस्थित ग्रामीणों को यह भी अवगत कराया गया कि आबादी क्षेत्र में 4 लेन सड़क निर्माण का निर्णय यातायात की सुविधा, सड़क सुरक्षा एवं भविष्य की आवश्यकताओं के तकनीकी परीक्षण के उपरान्त किया गया है, इसमें किसी प्रकार के बदलाव तकनीकी दृष्टि से स्वीकार नहीं है।

इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना सड़क के प्रावधानों के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए सड़क विकास को जनहित में आवश्यक बताया गया तथा निर्माण कार्य में पूर्ण योगदान देने की बात कही। अंत में उपस्थित सभी ग्रामीणों एवं अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


06/03/22

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान : वीटन, दिनांक : 06.07.2022, समय : 11:00 AM

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
1.	ओमप्रकाश	वीटन	8000210163	ओमप्रकाश
2.	मनोरम	वीटन	9649398979	मनोरम
3.	किमला	वीटन		
4.	रुपा	वीटन		
5.	तापन	गगनपुर	7611068452	तापन
6.	रामदेव	वीटन	7014759832	रामदेव
7.	जगदीशसिंह	वीटन	9784381259	जगदीशसिंह
8.	भरसिंह	चौहाननगर	9829277262	भरसिंह
9.	रामअवतार	वीटन	9541955312	रामअवतार
10.	किशोरसिंह	चौहाननगर	9928119005	किशोरसिंह
11.	मंगलाराम डिडेला (सरपंच प्रतिनिधि)	इन्दौर	9828335551	
12.	विश्वराम	वायड	9982448555	विश्वराम
13.	रामकृष्ण	वायड	9983459424	रामकृष्ण
14.	वीरमाराज	वीटन	1377389765	वीरमाराज
15.	राजेश	वायड	900647333	राजेश

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान : बीरन

दिनांक

: 06.07.2022 समय

: 11:00 AM

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
16	रामनिवास	बीरन	9001253201	रामनिवास
17	भाकरराम	"	8432053611	भाकरराम
18	दशराम कडि शारदा	बीरन	9166021871	दशराम
19	प्रेमराम	बीरन	9587752533	प्रेमराम
20	शेखरराम	बीरन	9351759580	शेखरराम
21	जयशारदा	बीरन	9784621633	जयशारदा
22	काकुलाल	बीरन	9461267129	काकुलाल
23	बन्सराम	बीरन		
24	जुतरराम	बीरन		
25	सुभाकरराम	बीरन	9358015433	सुभाकरराम
26	दुगारराम	बीरन		दुगारराम
27	हरिराम	बीरन		
28	जगदीशराम	बीरन	6378285599	जगदीशराम
29	महेश महेशलाल	बीरन		
30	शमकरराम	बीरन	9610546566	शमकरराम

Rajiv Gandhi Sewa Kendra, Bitan
Date: 06.07.2022



राजस्थान सरकार

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.पी.पी.), पी.आई.यू- जोधपुर

जिला-जोधपुर, तहसील-बिलाड़ा में राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी) के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्ति अन्तर्गत अधिनियम, 2013 की धारा-5 एवं नियम, 2016 के नियम-7 के प्रावधानानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन (एस0आई0ए0) के तहत जनसुनवाई

तहसील-बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

स्थान: पंचायत भवन बिनावास, दिनांक: 07/07/2022, समय: प्रातः 11 बजे

उपस्थित अधिकारी:-

क्र0सं0	नाम	पद/विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
①	भगवती सिंह	S.D.M., Bilasa	7795944842	
(2)	मिना मीना	डी.पी.पी. ज.पी.पी.	9928279690	
(2)	प्रिया कवाड़िया	A.E., PWD,	8386048030	Pritya K...
(3)	अशोक गजदार	यू.ए.ए.कॉन्स्ट्रक्शन	9460156271	
(4)	श्रीराम शर्मा	य.पी.पी.	94145-22800	
(5)	अपदास वर्मा	V.D.O.	9418461290	अपदास वर्मा

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 07.07.2022 को प्रस्तावित सड़क परियोजना राज्य राजमार्ग संख्या - 21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़ - मेंड़ता सिटी) के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन एवं संभावित प्रभाव के परिमाण को निर्धारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी महीदय बिलाड़ा की अध्यक्षता में जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम-बिनावास के संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों ने भाग लिया। जनसुनवाई के दौरान परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजना, निजी

भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव तथा परियोजना कार्यान्वयन हेतु लागू होने वाले नीति-नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पश्चात् संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों से उक्त परियोजना सड़क हेतु तैयार प्रस्तावित भूमि अवाप्त योजना से उनको होने वाले समस्याओं और सुझाओं को व्यक्त करने का अनुरोध किया गया।

इस क्रम में ग्राम बिनावास के संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने भूमि अवाप्त योजना जो कि वर्तमान जंक्शन विस्तार की आवश्यकता व्यक्त की एवं अवाप्त होने वाली भूमि का नियमानुसार उचित मुआवजा तथा जंक्शन पर नए बस निर्माण की मांग करते हुए उस पर सरकारी / निजी बसों के ठहराव हेतु अनुरोध किया गया। उक्त मांग एवं सुझाव पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि नए बस स्टैंड का निर्माण परियोजना में शामिल कर लिया जावेगा एवं अधिनियम 2013 एवं नियम 2016 के प्रावधानानुसार अवाप्त होने वाली भूमि का नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जायेगा तथा उपखण्ड अधिकारी महोदय विलास द्वारा बिनावास बस स्टैंड पर बसों के ठहराव हेतु सरकारी एवं निजी बस संचालकों से बात कर इस पर जल्द कार्यवाही करने हेतु आश्वासन दिया गया।

इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी संभावित
परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित
ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना सड़क
के प्रावधानों प्रति सहमति व्यक्त करते
हुए सड़क विकास को जनहित में
आवश्यक बताया गया तथा निर्माण कार्य
में पूर्ण योगदान देने की बात कही।
अंत में उपस्थित सभी ग्रामीणों एवं
अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए
जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

21
Dr. M. K. Sharma
21/12/2022
उप सचिव अधिकारी
विभाग

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान : बिगावाड़, दिनांक : 1.7.2022, समय : 11 AM

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
①	ब्याडू लाल वर्डिफंज ५	बिगावाड़	8107696753	ब्याडू लाल
②	शनिेश मेघवाल ग्राम राजगार सहारनूर	शा. पं. कीनवास	8619328813	शनिेश
③	रामलाल शर्मा	बिगावाड़	9414119462	रामलाल
④	हौलाराम सरगार जलधर खिलार	२/१	9001036009	हौलाराम
⑤	उषाकुमारी ग्राम साफि	—	9602531343	उषा
⑥	ब्रजपाल वैष्णव	— वि. ३०	9413461290	ब्रजपाल
⑦	प्रकाश	बिगावाड़	9166936922	प्रकाश
⑧	ब्रजशम	बिगावाड़		ब्रजशम
⑨	सुंदरशम	बिगावाड़	9414127048	सुंदरशम
⑩	बिनाशम	बिगावाड़	9214874473	बिनाशम
⑪	गो विन्द	बिनाशम	7370082812	गो विन्द
⑫	हृदय २१५	बिगावाड़	73576508 34	हृदय
⑬	श्यामलाल	बिगावाड़	8003514075	श्यामलाल
⑭	जितेंद्र	बिगावाड़	7073161150	जितेंद्र
⑮	पैमाराम	बिगावाड़	9530124459	पैमाराम

Panchayat Bhawan, Binabas
Date: 07.07.2022

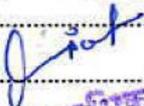


जनसुनवाई के दौरान परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजना, निजी भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव तथा परियोजना कार्यान्वयन हेतु लागू होने वाले नीति-नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पश्चात् संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों से उक्त परियोजना सड़क हेतु तैयार प्रस्तावित भूमि अवाप्त योजना से उनको होने वाली समस्याओं और सुझाओं को व्यक्त करने का अनुरोध किया गया।

इस क्रम में ग्राम बांकलिया के संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने भूमि के बदले भूमि की मांग की, ग्राम जवासिया के ग्रामीणों ने वर्तमान स्टेट हाईवे सड़क पर स्थित निजी खातेदारी भूमि के खातेदारों द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य अर्न्तगत प्रभावित होने वाले भू-भाग का मुआवजा प्रदान करने की मांग की तथा कुछ ग्रामीणों ने सड़क निर्माण अर्न्तगत प्रभावित खसरे की पुनः जाँच कर अग्रिम कार्यवाही करने की मांग रखी। उक्त सभी समस्याओं और सुझाओं पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि उक्त परियोजना सड़क हेतु अवाप्त की जा रही निजी भूमि का अधिनियम, 2013 एवं नियम, 2016 के तहत निर्धारित बाजार दर पर अवाप्त भूमि का प्रतिस्थापन लागत पर भूमि के लिए नियमानुसार मुआवजे का ही प्रावधान किया गया है, इसलिये भूमि के बदले निर्धारित मुआवजा

ही देय है। ग्राम जवासिया में वर्तमान स्टेट हाईवे सड़क पर स्थित निजी खातेदारी भूमि के खातेदारों का वर्तमान रास्ते संबंधी समस्याओं के प्रकरण के तहत आता है, इस संबंध में बंदोबस्त एवं राजस्व विभाग को लिखित रूप से सूचित किया गया है, जोकि प्रक्रियाधीन है। अतः उक्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय देने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सड़क निर्माण अर्न्तगत प्रभावित खसरां की पुनः जांच के संबंध में ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि इसे अधिनियम के तहत धारा- 11 की कार्यवाही से पूर्व राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रूप से परीक्षण कराया जा कर निष्पादित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना सड़क के प्रावधानों प्रति सहमति व्यक्त करते हुए सड़क विकास को जनहित में आवश्यक बताया गया तथा निर्माण कार्य में पूर्ण योगदान देने की बात कही। अंत में उपस्थित सभी ग्रामीणों एवं अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


उपनिर्देश अधिकारी
शिवपुर मंडल (जिला मुख्यालय)

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान : पीपाड़ बाहर दिनांक : 08.07.2022 समय : 11:00 AM

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
01	केल्याण शिंदे राशिंदे	जवाहरपुर	941338605	
02	गुमधारा	जिगेण	9462276852	
03	नरपतादे पापरी	जिगेण	9829796174	
04	शमनि वाम शोका	वाकलिया	6378002061	शमनि वाम
05	परसारा	कांकलिया	9784258044	परसारा
06	काकडरा	जवाहरपुर	96027-35633	
07	श्यामल	रिमां देवोमी	9795457016	
08	देवारा (उधाल)	रिमां देवोमी	9461990105	
09	धर्मम माली	पीपाड़-बाहर	9680303539	धर्मम
10	शोखलाल गहलोत	पीपाड़-बाहर	9414702913	शोखलाल
11	हेमारा	वाकलिया	963662128	हेमारा
12	शिवानराम	वाकलिया	7790906846	शिवानराम
13	शंकरका	जवाहरपुर	6350186115	
14	शंकरका	दिमा	90245-87973	
15	शंकरका	वाकलिया	9660771482	

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान :, दिनांक :, समय :

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
	Mohd. Yousaf	पीपाड़	9414612440	(Signature)
	जयराम परिवार	बीवाकलिया	8003327324	जयराम
	उदराम	बीवाकलिया		उदराम
	अमित कुमार	बीवाकलिया	9828656720	
	डामिके जौजला	बीवाकलिया	9929568112	(Signature)
	सोहन लाल	जवालिया	9413578274	सोहन लाल
	अमरराम काशी	पीपाड़	9414135813	(Signature)
	गुरे सुधीर राम	पीपाड़	941464467	(Signature)

Panchayat Samiti Sabhagar, Pipad
Date: 08.07.2022



राजस्थान सरकार

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.पी.पी.), पी.आई.यू- जोधपुर

जिला-जोधपुर, तहसील-पीपाड़ शहर में राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी) के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्ति अन्तर्गत अधिनियम, 2013 की धारा-5 एवं नियम, 2016 के नियम-7 के प्रावधानानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन (एस0आई0ए0) के तहत जनसुनवाई

तहसील-पीपाड़ शहर, जिला-जोधपुर

स्थान: राजीव गांधी सेवा केन्द्र, नानण, दिनांक: 08/07/2022, समय: दोपहर 1 बजे

उपस्थित अधिकारी:-

क्र0सं0	नाम	पद/विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
(1)	Padma Devi	SOM	8290308134	[Signature]
(2)	Pritya Kauria	A.En, PPP, PWD	8386048030	[Signature]
(3)	जोधिया	अध्यक्ष, पी.पी.पी.	9602489337	[Signature]
(4)	Kuldeep Singh	AMC	9887233997	[Signature]
(5)	DRS WGH	RI Kosam	8107409968	[Signature]

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 08.07.2022 को प्रस्तावित सड़क परियोजना राज्य राजमार्ग संख्या - 21 (दांतीवाड़ा - पीपाड़ - मेंड़ता सिटी) के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन एवं संभावित प्रभाव के परिमाण को निर्धारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी महोदय पीपाड़ शहर की अध्यक्षता में जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम खुड़ेचा, नानण, जालीवाड़ाखुर्द, जालीवाड़ाकलाँ एवं मालावास के संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों ने भाग लिया। जनसुनवाई के दौरान

परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजना, निजी भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव तथा परियोजना कार्यान्वयन हेतु लागू होने वाले नीति-नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पश्चात् संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों से उक्त परियोजना सड़क हेतु तैयार प्रस्तावित भूमि अवाप्त योजना से उनको होने वाली समस्याओं और सुझाओं को व्यक्त करने का अनुरोध किया गया।

इस क्रम में ग्राम खुड़ेचा एवं नानण के संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने भूमि अवाप्त योजना जोकि धनी आबादी के बचाव हेतु बाईपास निर्माण से संबंधित है को जनहित में मानते हुए अवाप्त होने वाली भूमि का नियमानुसार उचित मुआवजा भुगतान करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करने की मांग की। इसके अतिरिक्त कुछ खातेदारों ने गाँव की डी.एल.सी. दर काफी कम होने की चिंता व्यक्त की तथा बाईपास निर्माण के परिणामस्वरूप खेतों के दो फाड़ होने की दशा में सिंचाई व अन्य कृषि कार्य बाधित होने की बात रखी गई। उक्त सभी समस्याओं और सुझाओं पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रस्तावित बाईपास के निर्माण का कार्य अधिनियम, 2013 एवं नियम, 2016 के प्रावधानानुसार अवाप्त भूमि का

मुआवजा निर्धारित व निर्धारित राशि का भुगतान करने के उपरान्त ही किया जायेगा, इसके अतिरिक्त नियमानुसार मुआवजे हेतु निर्धारित बाजार दर पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दूरी का गुणक फेक्टर व 100 प्रतिशत सोलेशियम व नियमानुसार व्यय को शामिल कर भूमि का मुआवजा दिया जायेगा। बाईपास निर्माण के परिणामस्वरूप खेतों के दो फाड़ होने की दशा में सिंचाई व अन्य कृषि कार्य बाधित न हो, इसके लिए परियोजना स्तर पर निर्माण के दौरान उचित व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना सड़क के प्रावधानों के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए सड़क विकास को जनहित में आवश्यक बताया गया तथा निर्माण कार्य में पूर्ण योगदान देने की बात कही। अंत में उपस्थित सभी ग्रामीणों एवं अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

Praveen
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर महानगर (जोड़पुर)

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान :, दिनांक :, समय :

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
1	Bhopal Ram	NANAN	9928343414	Bhopal
2	चर्मणु	नानग	95715 77490	चर्मणु
3	pemaram	नानग	8262.86.20 3571 57	pemaram
4	Mohan Ram	NANAN	979967 0109	मोहनराम
5	सुजारांम	जालिका	8619994069	सुजारांम
6	समुन्दर सिंह	जालिका	9784173662	समुन्दर सिंह
7	दौलाराम जी	जालिका		दौलाराम जी
8	बस्ताराम जी	जालिका	9636118684	
9	दशरथ दासी	नानग	9413865965	दशरथ
10	भागीरथ	नानग	8764118799	भागीरथ
11	श्यामलाल कुडुला	मालिका	9799682253	श्यामलाल
12	शिवश्याम दाधिक	नानग	9413129528	शिवश्याम
13	मुनाराम/जोषाराम	नानग		मुनाराम
14	फारुश/हरिराम	नानग	8560044069	फारुश
15	केशवलाल/रमेशचण्ड	नानग	9782040021	केशवलाल



राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान :, दिनांक :, समय :

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
16	भूपेन्द्र सिंह	नानन	9983450031	
17	पलपुराम माली	जालीवाड़ा कला	995282395	पलपुराम माली
18	करनी दान चारके	जालीवाड़ा खुर्द	7568801195	
19	भीमराज माली	जालीवाड़ा कला	9571408661	
20	भागिरथ देवारी	जालीवाड़ा खुर्द	916614376	भागिरथ
21	पूजाशरत देवारी	जालीवाड़ा खुर्द	7568440383	पूजाशरत
22	किशनाराम देवारी	जालीवाड़ा खुर्द	8079031310	Kishan Deewari
23	Shr Devesh	Nanan	9414125665	Shr
24	Ranveer	Nanan	7742926300	Rudh
25	Suresh Sankhul	Nanan	9929081117	
26	Surell Sadech	Nanan	98298 94327	Surell
27	पपुराम जी गदलोत	मालीवाड़ा	9549677075	श्यामलाल
28	ARVIND SINGH	JALIPARA	8118863534	
29	जोधावाड़ा	जालीवाड़ा खुर्द	9602489337	
30	रामभिराज	खुर्दवा	9799681952	रामभिराज

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान :, दिनांक :, समय :

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
31	शिवप्रसाद	नानावा	9686723558	शिवप्रसाद
32	मोहनसिंह	नानावा	-	मोहनसिंह
33	जगन्नाथसिंह	नानावा	9460468145	जगन्नाथ
34	श्रीरामलक्ष्मी	खुंटी	99283-7353	श्रीराम
	केशवसिंह	नानावा	99281089 45	केशवसिंह
	मकरसिंह	मकरसिंह		मकरसिंह
	बाबुलाल	जालीवाड़ा	902496 4911	बाबुलाल
	अखिल	नानावा	63786-2094	अखिल
	DMSINGH	शु.अ.नि.	8107409968	डॉ.सिंह
	दुर्गासिंहजी	नानावा	8107099881	दुर्गासिंह
	मोहनसिंह	नानावा	9784883316	मोहनसिंह
	प्रतापराम	नानावा	-	प्रतापराम

Rajiv Gandhi Sewa Kendra, Nanan
Date: 08.07.2022



सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.पी.पी.), पी.आई.यू- जोधपुर

जिला-जोधपुर, तहसील-पीपाड़ शहर में राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी) के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि अवाप्ति अन्तर्गत अधिनियम, 2013 की धारा-5 एवं नियम, 2016 के नियम-7 के प्रावधानानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन (एस0आई0ए0) के तहत जनसुनवाई

तहसील-पीपाड़ शहर, जिला-जोधपुर

स्थान: राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मादलिया, दिनांक: 11/07/2022, समय: प्रातः 11 बजे

उपस्थित अधिकारी:-

क्र0सं0	नाम	पद/विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
(1)	Paalma Devi	SDM	8290308134	
(2)	Pritya Kavarina	A.En., PWD	8386048030	
(3)	Jagdish Meghwal	LUR	9468561895	
(4)	MAHENDRA SOLANKI	PATWARDI	8209992898	
(5)	MOH. YUSUF	PATWARDI	7073331247	

बैठक की कार्यवाही

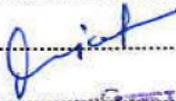
आज दिनांक 11.07.2022 को प्रस्तावित सड़क परियोजना राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा - पीपाड़ - मेंड़ता सिटी) के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन एवं संभावित प्रभाव के परिमाण को निर्धारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी महोदय पीपाड़ शहर की अध्यक्षता में जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम-मादलिया, गढ़सुरिया, भठादेवनगर एवं बोरुंदा के संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों ने भाग लिया। जनसुनवाई के दौरान

परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजना, निजी भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव तथा परियोजना कार्यान्वयन हेतु लागू होने वाले नीति - नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके पश्चात् संभावित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित ग्रामीणों से उक्त परियोजना सड़क हेतु तैयार प्रस्तावित भूमि अवाप्त योजना से उनको होने वाली समस्याओं और सुझाओं को व्यवक्त करने का अनुरोध किया गया। इस क्रम में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा कुल 12 आपत्तियां प्राप्त हुईं जोकि भूमि के नियमानुसार उचित मुआवजे, ग्राम गढ़सुरिया एवं बोरुन्दा में बाईपास निर्माण की मांग, वर्तमान स्टेट हाईवे सड़क पर स्थित निजी खातेदारी भूमि के खातेदारों द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य अर्न्तगत प्रभावित होने वाले भू-भाग का मुआवजा प्रदान करने की मांग, ग्राम - बोरुन्दा में सड़क के किनारे स्थित हरजीनाडा तालाब के पाल को नहीं तोड़ने तथा आबादी क्षेत्र में स्थित जाट समाज सेवा समिति के प्लॉट की मूल स्थिति एवं स्थान सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है। उक्त सभी समस्याओं और सुझाओं पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रस्तावित सड़क का निर्माण कार्य अधिनियम, 2013 एवं नियम, 2016

के प्रावधानानुसार अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित व निर्धारित राशि का भुगतान करने के उपरान्त ही किया जायेगा, परियोजना सड़क राज्य राजमार्ग संख्या - 21 (दांतीवाड़ा - पीपाड़ - मेंड़ता सिटी) के विकास हेतु अनुमोदित प्लान प्रोफाइल (सड़क निर्माण डिजाइन) अन्तर्गत ग्राम गढ़सुरिया एवं बोरुन्दा में बाईपास स्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिये सड़क सीमा में प्रभावित सभी श्रेणियों के निर्माण / संरचनाओं का मूल्यहास के बिना प्रतिस्थापन लागत के समतुल्य निर्धारित दर पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पात्रता मैट्रिक्स के प्रावधानानुसार मुआवजा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रभावित सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का आवश्यकतानुसार स्थानांतरण एवं बहाली का कार्य परियोजना द्वारा लोगों से विचार-विमर्श कर किया जायेगा। वर्तमान स्टेव हाईवे सड़क पर स्थित निजी खातेदारी भूमि के खातेदारों का वर्तमान रास्ते संबंधी समस्याओं के प्रकरण के तहत आता है, इस संबंध में बंदीबस्त एवं राजस्व विभाग को लिखित रूप से सूचित किया गया है, जोकि प्रक्रियाधीन है, अतः उक्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ग्राम- बोरुन्दा में सड़क के किनारे स्थित हरजीनाडा तालाब पर बनी पाल सड़क

के संरक्षण में आवश्यकता के दृष्टिगत
आंशिक रूप से प्रभावित होगी, किन्तु
तालाब को सुरक्षित करने हेतु सुरक्षा दीवार
का प्रावधान परियोजना में सम्मिलित कर
लिया जावेगा साथ ही आबादी क्षेत्र में
स्थित जाट समाज सेवा के प्लाट को
सुरक्षित करने का प्रयास किया जायेगा
और यदि निर्माण कार्य के दौरान अत
प्लाट पर कोई प्रभाव पड़ता है तो
नियमानुसार कार्यवाही कर प्रभाव को कम
किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी
संभावित परियोजना व्यक्तियों एवं संबंधित
ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना सड़क
के प्रावधानों प्रति सहमति व्यक्त करते
हुए सड़क विकास को जनहित में
आवश्यक बताया गया तथा निर्माण कार्य
में पूर्ण योगदान देने की बात कही।
अंत में उपस्थित सभी ग्रामीणों एवं
अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए
जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


उपसहस्र अधिकारी
विभाग (जीएचए)

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान :, दिनांक :, समय :

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
	बैकशराम	मादलीया	954964 0 304	
	गोपलदास	मादलीया	707343799	गोपलदास
	उदाराध	मादलीया		उदाराध
	मंसूराम	कोर-दा	94604326 14	मंसूराम
	शिवराम	कोर-दा	95552068	शिवराम
	लक्ष्मीदास	बोर-दा	9414703917	लक्ष्मीदास
	जगदरसिंह (कोर-दा)	मादलीया	9414412162	
	नरेश दास	कोर-दा	9602964392	नरेश
	जगदरसिंह	कोर-दा	9414849 391	जगदरसिंह
	जबरसिंह	कोर-दा	9414703813	Jabarr Singh
	गुंडाराम कासगिया	जबलपुरिया	9928558322	GURU
	कुलदीप-दास	जबलपुरिया	8233933323	Kuldeep
	गीतदास-दास	जबलपुरिया	9145972731	गीतदास
	वीकरराम	बोर-दा	946550699	वीकरराम
	पुकार-दास	कोर-दा	9414117551	

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान :, दिनांक :, समय :

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
	किशोर दास	जठसुरीया	937022188	किशोर
	कुनम दास	जठसुरीया	7665740679	कुनम दास
	उममदराम	बोखडा	9414132938	
	दिलीप	बोखडा	9414108635	दिलीप
	दिराराम	मादलिया	9571538733	दिराराम
	उमेश	मादलिया	-	
	मुकुेश	बोखडा	8562090888	मुकुेश
	कपेश	बोखडा	8104570608	कपेश
	कपेश	बोखडा	8696929840	कपेश
	अशोक	बोखडा	7610058017	अशोक
	विश्वराम	बोखडा	-	
	लामा सिंह	बोखडा	7728018132	लामा
	नाथ सिंह	बोखडा	979914799	नाथ सिंह
	दिलीप सिंह	बोखडा	9799513264	दिलीप सिंह
	सुरेश सिंह	बोखडा	809449105	सुरेश सिंह

राज्य राजमार्ग संख्या-21 (दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेंड़ता सिटी)

ग्रामीणों की उपस्थिति पत्रक

स्थान : दिनांक : समय :

क्र० सं०	नाम	ग्राम	संपर्क नं०	हस्ताक्षर
	मधुसूदन	बोरुन्दा	987574 4775	मधुसूदन
	Hemant s/o Chaterbhysji Village Borunda	Borunda	7976710372	Hemant
	रामेश्वर दाधीच दाक पुन-साभना 30307	बोरुन्दा	9460602406	रामेश्वर
	श्याम सिंह मेडिया 90200 नम सिंह	बोरुन्दा	9982251000	श्याम
	दिलीप भवरीमा	बोरुन्दा	9413194928	दिलीप
	जीवन राम माली	मादलिया	9413523101	जीवन
	महिपाल खंदस	7014483993	महिपाल
	दिवेश चौधरी	756827968	दिवेश चौधरी
	चिमन राम	मादलिया	941376677	चिमन
	मोहन लाल	मादलिया	982965933	मोहन
	अनार राम रेखा	मादलिया	982965933	अनार

Rajiv Gandhi Sewa Kendra, Mandliya
Date 11.07.2022



Appendix 8: Terms of Reference (TOR) for the NGO/agency to assist PIUs in Resettlement Plan Implementation

A. Project Background

1. The government of Rajasthan has proposed to upgrade its road network under Rajasthan State Highway Investment Program (RSHIP) and as part of this endeavour, the Public Works Department (PWD) of Rajasthan has been mandated to undertake improvement and up-gradation of various State Highways and Major District Roads at different locations in Rajasthan. As part of this mandate, the PPP Division of Rajasthan Public Works Department has identified the roads requiring improvement that would improve the connectivity to national highways, major towns, and industrial belts. The proposed investment program will support the up-gradation and improvement of the identified roads and Tranche-III will finance 4 road projects totalling about 290.515 Km spread across the State of Rajasthan.

2. The Public-Private Partnership (PPP) Cell of the Public works Department has prepared the Resettlement Plan (RP) for Dantiwara-Pipar-Merta City SH 21 proposed under Tranche-3 for improvements under RSHIP. This RP addresses social issues arising out of the acquisition of land and other assets, eviction of squatters, and removal of encroachments resulting in social and/or economic displacement to households/individuals/community, either direct or indirect and is in compliance with ADB's Safeguard Policy Statement, 2009 and Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

3. A Resettlement Plan (RP) has been prepared to assist the affected people to improve or at least restore their living standards to the pre-project level. This RP captures the involuntary resettlement impacts arising out of the proposed improvements to the road Dantiwara-Pipar-Merta City SH 21 of RSHIP. The document describes the magnitude of impact, mitigation measures proposed method of valuation of land, structure and other assets, eligibility criteria for availing benefits, baseline socio-economic characteristics, entitlements based on the type of loss and tenure, the institutional arrangement for delivering the entitlements and mechanism for resolving grievances and monitoring.

4. The PMU has decided to call in for the services of RP implementation support agency/NGO experienced in carrying out such rehabilitation and resettlement activities at the grass-root level to assist the PIUs in RP implementation.

B. Objectives of the Assignment

5. The NGO shall assist the PPP Division, PWD(R), Rajasthan in the implementation of the Resettlement Plan for Tranche-3 Road subprojects grouped as four packages and comprising of 4-road subprojects and shall undertake the following tasks:

- Educating the DPs on their rights to entitlements and obligations.
- To ensure that the DPs are given the full entitlements due to them, according to the entitlements in the RP.
- To provide support and information to DPs for income restoration.
- Assist the DPs in relocation to resettlement site and rehabilitation, including counselling, and coordination with local authorities/line departments.
- Assist the DPs in redressing their grievances (through the grievance redress committee set up for the subproject)
- To assist the Project Implementation Unit (PIU) with the social responsibilities of the subproject, such as compliance with labour laws, prohibition of child labor, and gender issues.
- To conduct an awareness program on HIV/AIDs, Health and Hygiene, and Human Trafficking in affected villages.
- To collect data and submit progress reports on a monthly and quarterly basis for PIU to monitor the progress of RP implementation.

C. Scope of Work

a) Administrative Responsibilities of the NGO

- Working in coordination with the PD, PIU; and assisting the PD in carrying out the implementation of the RP;
- To assist the DPs in redressing their grievances through the GRCs;
- Assist the PIU in disclosure, conducting public meetings, information campaigns during the RP implementation, and giving full information to the affected community;
- Translate the summary of RP in local language for disclosure and disseminate to DPs;
- To assist the PIU in ensuring that the contractors comply with the applicable labour laws (including prohibition of child labour, bonded labour and gender requirements) as contained in the contract document;
- To assist the PIU in ensuring compliance with safety, health and hygiene norms, and the conduct HIV/AIDS and Human Trafficking awareness/prevention campaigns;
- Submit monthly and quarterly progress report to the PIU including both physical and financial progress. The report should also cover implementation issues, summary of grievances and summary of consultations.
- Provide data and information that PIU will require in the management of the data base of the DPs.
- Assist PIU in providing training to DPs, wherever required in the implementation of RP.

b) Responsibilities for Implementation of the RP

- Agency/NGO shall verify the information already contained in the RP and the individual losses of the DPs. They should validate the data provided in the RP and report to PIU on changes required, if any, along with documentary evidence.
- Wherever required, update the census and socioeconomic survey data and administer the census and socioeconomic survey questionnaire, if there are DPs who have been not covered during baseline survey and in particular the titleholders from whom land is being acquired.
- The Agency/NGO shall establish rapport with DPs, consult and provide information to them about the respective entitlements as proposed under the RP, and distribute entitlement cum Identity Cards to the eligible DPs. The identity card should include a photograph of the DP, the extent of loss suffered, the entitlement and contact details of the PIU, NGO and GRC.
- The Agency/NGO shall develop rapport between the DPs and the Project Director, PIU. This will be achieved through regular interactions with both the PIU and the DPs. Meetings with the PD, PIU will be held at least fortnightly, and meetings with the DPs will be held monthly, during the entire duration of the assignment. All meetings and decisions taken shall be documented by the NGO/Agency.
- Prepare monthly action plans with targets in consultation with the PIU.
- The Agency/NGO shall prepare micro plan detailing the type of impact and entitlements for each DP and display the list in prominent public places like villages, Panchayat offices, etc. prior to R&R award enquiry.
- During the verification of the eligible DPs, the Agency/NGO shall ensure that each of the DPs are contacted and consulted either in groups or individually. The Agency/NGO shall specially ensure consultation with women from the DPs families especially women headed households.
- Participatory methods should be adopted in assessing the needs of the DPs, especially with regard to the vulnerable groups of DPs. The methods of contact may include village level meetings, gender participation through group's interactions, and individual meetings and interactions.
- The Agency/NGO shall explain to the DPs the provisions of the policy and the entitlements under the RP. This shall include communication to the roadside squatters and encroaches about the need for the timely shifting/relocation to resettlement site, the timeframe for disbursement of their entitlement.
- The Agency/NGO shall disseminate information to the DPs on the possible consequences of the project on the communities' livelihood systems and the options available, so that they do not remain ignorant.

- Agency/NGO will monitor the civil construction work in each package to ensure there is no bonded/child labour.
 - In all of these, the Agency/NGO shall consider women as a special focus group, and deal with them with care and sympathy.
 - The Agency/NGO shall assist the project authorities in ensuring a smooth transition (during the part or full relocation of the DPs), helping the DPs to take salvaged materials and shift. In close consultation with the DPs, the Agency/NGO shall inform the PIU about the shifting dates agreed with the DPs in writing and the arrangements desired by the DPs with respect to their entitlements.
 - The Agency/NGO shall assist the DPs in opening bank accounts explaining the implications, the rules and the obligations of a joint account and how s/he can access the resources s/he is entitled to.
- c) Accompanying and Representing the DPs at the Grievance Redressal Committee (GRC) Meetings**
- The Agency/NGO shall nominate a suitable person (from the staff of the NGO) to assist the DPs in the GRC.
 - The Agency/NGO shall make the DPs aware of the existence of grievance redressal committees (GRCs)
 - The Agency/NGO shall help the DPs in filling the grievance application and also in clearing their doubts about the procedure as well as the context of the GRC award.
 - The Agency/NGO shall record the grievance and bring it to the notice of the GRCs within seven days of receipt of the grievance from the DPs. It shall submit a draft note with respect to the particular grievance of the DP, suggesting multiple solutions, if possible, and deliberate on the same in the GRC meeting with the permission of the Chair of the GRC.
 - To accompany the DPs to the GRC meeting on the decided date, help the DP to express his/her grievance in a formal manner if requested by the GRC and again inform the DPs of the decisions taken by the GRC within 3 days of receiving a decision from the GRC.
- d) Carry out Public Consultation**
- In addition to counseling and providing information to DPs, the Agency/NGO will carry out periodic consultation with DPs and other stakeholders
 - Should organise meetings and appraise the communities about the schedule /
 - progress of civil works
 - All the consultations should be documented and if possible, photographs and attendance sheets should be compiled. The list of participants and a summary of the consultations and outcome should be submitted to PIU.
- e) Assisting the PIU with the Project's Social Responsibilities**
- The Agency/NGO shall assist the PIU to ensure that the Contractors are abiding by the various provisions of the applicable laws pertaining to labour standards.
 - The Agency/NGO shall assist the PIU to implement HIV/AIDS awareness measures, including collaboration with the line agencies.
 - The Agency/NGO will assist the PIU in conducting the R&R award enquiry
 - Assist the PIU to incorporate changes in the micro plan, if any based on R&R award and resubmit the same to PIU for verification, endorsement and onward transmission to Additional Collector for disbursement.
- f) Monitoring and Reporting**
6. The RP includes provision for monitoring by PIU and quarterly, mid-term, and post-project monitoring and evaluation by external agency. The Agency/NGO involved in the implementation of the RP will be required to supply all information, documents to the external monitoring consultants.

D. Documentation and Reporting by NGO

7. The NGO selected for the assignments shall be responsible to:

- Submit an inception report within three weeks; on signing up of the contract including a work plan for the whole contract period, staffing and personnel deployment plan.
- Prepare monthly progress reports to be submitted to the PIU, with weekly progress and work charts as against the scheduled timeframe of RP implementation.
- Prepare and submit quarterly reports on a regular basis, to be submitted to the PIU.
- Submit a completion report at the end of the contract period summarizing the actions taken during the project, the methods and personnel used to carry out the assignment, summary of support/assistance given to the DPs, lessons learnt, best practices and suggestions, if any, for effective implementation.
- All other reports/documentation as described in these terms of reference.
- Record minutes of all meetings.
- Four copies of each report shall be submitted to PIU together with one soft copy of each report in the CD

E. Data, Services and Facilities to be provided by the Client

8. The PIU will provide to the NGO the copies of the RP, DPs' Census records and structure photographs, the strip plan of final design and any other relevant reports/data prepared by the DPR consultants. All facilities required in the performance of the assignment, including office space, office stationery, transportation and accommodation for staff of the Agency/NGO, etc., shall be arranged by the NGO.

F. Timeframe for Services

9. It is estimated that the NGO services will be required for about 36 months with intermittent inputs of key-personnel, to undertake the assignment of facilitating the implementation of the RP. The inputs of key personnel should be in accordance with the tasks and the corresponding time required for their completion. The time schedule for completion of key tasks is given below

No.	Task Description	Time for completion
1	Inception Report	the end of the 3rd week after commencement of services
2	Joint verification, issue of identity card and submission of corrected data, if any, including proposal for replacement and upgradation of community assets Additional and /or missing census survey records of DPs (to be collected only after due approval of such cases by RO in writing) including profiles of DP in such survey	the end of the 2nd month after commencement of services the end of the 3rd month after commencement of services
3	Monthly Progress Report /Quarterly Progress Report covering the activities in the scope of works and corresponding deliverables	7 days from the end of each month /quarter
4	Facilitating disbursement of the entitlements for 50% of total DPs in the 1st milestone coinciding with the milestone sections fixed by PIU	the end of the 5th month after commencement of services
5	Disbursement of the entitlements for the remaining DPs in the 1st milestone	the end of the 6th month after commencement of services
7	Disbursement of the entitlements for remaining DPs in the 2nd milestone Facilitating resettlement of DPs to the resettlement site(s)	the end of the 15th month after commencement of services
8	Final Report summarising the action taken and other resettlement works to be fulfilled by the NGO	one month before the service / 35th month after commencement of services

No.	Task Description	Time for completion
9	Final report summarising the action taken and other resettlement works to be fulfilled by the NGO	the end of the service / 36th month after commencement of services incorporating suggestions of PIU on the draft report.

G. Team for the Assignment

10. The Agency/NGO shall assign a team of professionals for assisting PIU in RP implementation. The Agency/NGO team should consist of the following 5-core professionals and a minimum of 4 support staff including a skilled data entry operator. The core team should have a combined professional experience in the areas of social mobilization, community development, land acquisition and resettlement, census and socioeconomic surveys and participatory planning and consultations.

No	Key Professional	No. of persons	Experience
1	Team Leader cum R&R expert (intermittent input)	1	Postgraduate in Social Science with a minimum of 10 years' experience in R&R, with land acquisition and R&R implementation experience in 5 projects of which at least 3 should be linear projects (Highway) funded by external agencies. Should be proficient in Hindi and English
2	R&R Expert and Field Coordinator (intermittent input)	4	Graduate in Social Science with knowledge and experience in census and socioeconomic surveys, RP implementation PRA Technique and fluent in Hindi and English. Should have a minimum of 5 years' experience in R&R, with land acquisition and R&R implementation experience in 3 projects of which at least 2 should be linear projects (Highway) funded by external agencies. One field coordinator should be posted for each of the road subproject in this packager

H. Payment Terms

11. The payment will be made corresponding to the tasks described under 'Timeframe for Services' above. For awareness campaigns on HIV-AIDS, health and hygiene, the PIU will provide funds separately at actuals, based on specific campaign proposals submitted by the NGO. Cost of printing disclosure material will be paid by PIU directly or PIU will make available printed disclosure material.

12. The financial quote should include remuneration of key personnel and support staff, and all costs related to carrying out the services, excluding cost of awareness campaigns for HIVAIDS, health and hygiene, printing of disclosure handouts and printing and laminating identity cards for DPs. Service tax, if applicable, will be paid by PIU and proof of remittance should be submitted to PIU after each payment is made. The NGO should cover their staff with adequate insurance and the cost shall be included in the financial quote under overheads.

Appendix 9: Terms of Reference for engaging an External Monitoring Agency/Expert

A. Project Description

1. The government of Rajasthan has proposed to upgrade its road network under Rajasthan State Highway Investment Program (RSHIP) and as part of this endeavor, the Public Works Department (PWD) of Rajasthan has been mandated to undertake improvement and up-gradation of various State Highways and Major District Roads at different locations in Rajasthan. As part of this mandate, the PPP Division of Rajasthan Public Works Department has identified the roads requiring improvement that would improve the connectivity to national highways, major towns, and industrial belts. The proposed investment program will support the up-gradation and improvement of the identified roads and Tranche-3 will finance 4 road projects totaling about 290.515 Km spread across the State of Rajasthan.

2. The Public-Private Partnership (PPP) Cell of the Public works Department has prepared the Resettlement Plan (RP) for Dantiwara-Pipar-Merta City SH 21 proposed under Tranche-3 for improvements under RSHIP. This RP addresses social issues arising out of the acquisition of land and other assets, eviction of squatters, and removal of encroachments resulting in social and/or economic displacement to households/individuals/community, either direct or indirect and is in compliance with ADB's Safeguard Policy Statement, 2009 and Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

3. A Resettlement Plan (RP) has been prepared to assist the affected people to improve or at least restore their living standards to the pre-project level. This RP captures the involuntary resettlement impacts arising out of the proposed improvements to the road Dantiwara-Pipar-Merta City SH 21 of RSHIP. The document describes the magnitude of impact, mitigation measures proposed method of valuation of land, structure and other assets, eligibility criteria for availing benefits, baseline socioeconomic characteristics, entitlements based on the type of loss and tenure, the institutional arrangement for delivering the entitlements and mechanism for resolving grievances and monitoring.

4. The PIUs have appointed agencies/NGO's to support the respective PIU in RP implementation. The subproject includes a provision for monitoring and evaluation of the implementation of the subproject resettlement plans by an external monitor/agency. Therefore, the PMU requires the services of a reputed individual/consultancy firm for monitoring and evaluation of RP implementation.

B. Scope of work – Generic

5. The scope of work includes:

- To review and verify the progress in resettlement implementation as outlined in the RP;
- To monitor the effectiveness and efficiency of PIU, and NGO in RP implementation;
- To assess whether resettlement objectives, particularly livelihoods and living standards of the Displaced Persons (DPs) have been restored or enhanced;
- To assess resettlement efficiency, effectiveness, impact, and sustainability, drawing both on policies and practices and to suggest any corrective measures, if necessary; and
- To review the project impacts on vulnerable groups, indigenous people, and groups and assess the effectiveness of the mitigative actions taken.

C. Scope of work- Specific

6. The major tasks expected from the external monitor are:

- To develop specific monitoring indicators for undertaking monitoring for RP implementation;
- Review results of internal monitoring and verify claims through random checking by adopting suitable sampling method at the field level to assess whether land acquisition/resettlement objectives have been generally met;
- Involve the affected people and community groups in assessing the impact of land acquisition for monitoring and evaluation purposes;
- Evaluate and assess the adequacy of compensation and R&R assistances given to the DPs, the resettlement sites developed and relocation process and the livelihood opportunities and incomes as well as the quality of life of DPs; and
- To evaluate and assess the adequacy and effectiveness of the consultative process with DPs, particularly those vulnerable, including the adequacy and effectiveness of grievance procedures and legal redress available to the displaced persons, and dissemination of information about these.

D. Time Frame and Reporting

7. The independent monitoring agency/expert will be responsible for overall monitoring of the RP implementation and will submit a quarterly review directly to PMU for onward transmission to ADB with PMU's comments.

E. Qualifications

8. The monitoring agency/expert will have significant experience in resettlement policy analysis and RP implementation. Further, work experience and familiarity with all aspects of resettlement operations would be desirable. The Team Leader / Expert should have the following qualification: (i) postgraduate degree in social science; (ii) 15 years experience in R&R; (iii) experience in ADB/WB funded R&R projects; and (iv) R&R monitoring experience in ADB/WB funded projects. Interested agencies/consultants should submit the proposal for the work with a brief statement of the approach, methodology, and relevant information concerning previous experience on monitoring resettlement implementation and preparation of reports.

9. The profile of the agency/expert along with the full CV of monitors to be engaged must be submitted along with the proposal.

F. Budget and Logistics

10. Copies of the proposal - both technical and financial - should be submitted and the budget should include all costs and any other logistics details necessary for resettlement monitoring.